MR. CHAIRMAN: The Government is not under my control. ...*(Interruptions)*... I connot dictate anything to the Government. ...*(Interruptions)*... I cannot dictate anything to the Government. ...*(Interruptions)*... The Government is here. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Let them give an assurance to the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question No. 65.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, Question Number 62 is there. He had raised a point. I presume, it is there on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: Question No. 62.

Sports infrastructure in rural areas

*62. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of sports infrastructure facilities in rural areas;

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to start an effective programme for youth of rural areas; and

(c) the details of the schemes under which financial assistance is provide for the promotion of sports in the country through NGOs and performance review of such schemes, particularly in Maharashtra State?

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) As 'Sports' is a State subject in the Constitution, the primary responsibility for the creation of sports infrastructure facilities throughout

the country, including the rural areas, falls on State Governments. Till 31.3.2005, the Ministry was supplementing the efforts of the State Governments for the creation of sports facilities in various States by providing assistance under the Centrally Sponsored Sports Infrastructure Schemes in accordance with the approved pattern subject to the receipt of viable proposals. With effect from 1.4.2005 however, the Sports Infrastructure Schemes were transferred to the State sector. The fresh cases of Sports Infrastructure projects will have to be funded by State Governments out of their own resources. All State Governments were informed accordingly in February, 2005. However, the Planning Commission has indicated that funds to the extent of committed liabilities will be provided for ongoing approved Sports Infrastructure projects during the remaining period of the Tenth Plan only. In recognition of the continuing acute, shortage of sports facilities in rural areas, thus denying the vast majority of children, adolescents and youth access to organized sports and games, consideration is being given to the promotion of a Panchayat Yuva Khel Abhiyan in collaboration with schools and other educational institutions, on the one hand, and with Panchayati Raj Institutions, on the other.

(c) The Ministry is implementing the scheme of Assistance to National Sports Federations. Under the scheme, Central assistance is provided to the recognized National Sports Federations, which are autonomous registered bodies, for purposes such as for participation in tournaments & Training abroad, organizing National/International Championships in India and purchase of Sports Equipments. These recognized Federations are National level bodies which are responsible for promotion of Sports in the country as a whole in consultation with their affiliated State Units. Government of India does not deal with State Level Sports Federations/ Associations and as such State-wise data are not maintained. The performances of the recognised NSFs are reviewed from time to time.

However, details of financial assistance provided to different States during the last three years under the erstwhile Scheme of "Grants for Creation of Sports Infrastructure" (including Maharashtra) is enclosed as Statement-I (*See* below). The figures indicated include grants released to NGOs in respective States.

Statement-I

State-wise details of Central assistance released under the Scheme of Grants for Creation of Sports Infrastructure from 2003-04 to 2005-06 (As on 31.3.2005)

(Rs. In lakhs)

Sl. No.	State/UT	2003-2004		2004-2005		2005-2006 (As on 31.3.2006)	
		Amount released	No. of projects	Amount released	No. of projects	Amount released	No. of projects
1.	Andhra Pradesh	484.527	14	123.75	7	45.00	1
2.	Arunachal Pradesh	191.00	5	27.00	1	71.00	1
3.	Assam	17	2	188.0	9	87.00	1
4.	Bihar	0	0	0	0	0	0
5.	Delhi	0	0	0	0	0	0
6.	Goa	0	0	0	0	0	0
7.	Gujarat	0	0	65.00	2	0	0
8.	Haryana	40.17	2	118.13	16	32.80	4
9.	Himachal Pradesh	100.21	8	118.63	10	0	0
10.	Jammu & Kashmir	26.82	18	22.50	1	0	0
11.	Karnataka	58.7	8	101.3	9	0	0
12.	Kerala	13.01	4	1.50	1	0	0
13.	Madhya Pradesh	152.27	13	115.40	6	18.00	1
14.	Maharashtra	238.43	13	169.04	9	45.08	2
15.	Manipur	0	0	22.50	3	0	0
16.	Meghalaya	100.11	5	234.55	5	0	0
17.	Mizoram	136.32	21	30.00	1	59.59	1
18.	Nagaland	962.46	21	115.98	12	45.00	1
19.	Orissa	0.05	1	0.75	1	0	0
20.	Punjab	45.00	1	0	0	0	0
21.	Rajasthan	25.00	2	8.72	1	23.00	1
22.	Sikkim	0	0	0	0	0	0
23.	Tamil Nadu	170.36	22	81.15	13	50.52	2
24.	Tripura	0	0	0	0	0	0
25.	Uttar Pradesh	46.94	3	69.23	6	83.00	4
26.	West Bengal	20.07	15	49.70	4	0	0
27.	Chhattisgarh	78.50	4	0	0	0	0
28.	Jharkhand	0	0	30.00	1	0	0
29.	Uttaranchal	0	0	94.80	5	0	0
30.	A&N Islands	0	0	0	0	0	0
31.	Chandigarh	0	0	0	0	0	0
32.	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0
33.	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0
34.	Pondicherry	0	0	0	0	0	0
35.	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
	TOTAL:	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19

श्री संजय राउत: सर, माननीय मंत्री जी ने माना है कि "It is a fact that there is acute shortage of sports infrastructure facilities in rural areas." Sir, sports is a neglected part of our total Budget. मंत्री जी ने जो ब्यौरा दिया है, यह उसमें स्पष्ट है कि 2003-04 में 2906.98 लाख रुपए केन्द्रीय सहायता जारी की गई, जो 2004-05 में घटकर 1787.99 लाख रुपए रह गई और 2005-06 में यह राशि सिर्फ 480 लाख रुपए रह गई । मैं जानना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स पर केन्द्र की तरफ से यह बजट क्यों घटता जा रहा है, क्या यह सरकार खेल को गंभीरता से देखती है या नहीं और अगर आपको खेल के लिए कुछ करना है तो सैंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट से खेल मंत्रालय को कितने फंड की जरूरत है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, माननीय सदस्य को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अनुसार खेल का विषय राज्यों से जुड़ता है, केन्द्र से नहीं। मुकम्मिल तौर पर स्टेट लिस्ट में खेल का ज़िक्र किया गया है। इसके बावजूद केन्द्र की तरफ से सैंट्रली स्पांर्स्ड स्मीम्स के जरिए हम राज्य सरकारों को मदद दे रहे थे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2005-06 से यह तय किया गया है कि चूंकि राज्य सरकारों की आमदनी काफी बढ़ गई है तो इस विषय की पूरी जिम्मेवारी उन्हीं को दी जाए। मैं मानता हूं कि हमारे ग्रामीण इलाकों में जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह काफी नहीं है और इसका मूल कारण है कि राज्य सरकारों ने ही पूरी तरह से उसे उपलब्ध नहीं करवाया। मेरी समझ में इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसलिए इसी जवाब में मैंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि अपने मंत्रालय में हम इस पर विचार कर रहे हैं कि एक पंचायत युवा खेल अभियान को शुरू किया जाए। हमारे यहां तकरीबन ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत हमारे यहां तकरीबन ढाई लाख यूथ क्लब्स हैं। इन दोनों को जोड़ कर यह देखा जाएगा कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकारें मिल कर किस तरह से आर्गनाइज्ड गेम्स और स्पोर्ट्स को ज्यादा बड़े पैमाने पर उपलब्ध करवा सकते हैं। इस कार्य को करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन ने हमें बताया है कि इस देश में कुल मिलाकर तकरीबन तीन करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खेल प्रसुविधाएं दी जा रही हैं। हमारा अनुमान है कि करीब दो करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जिनको यूथ और स्पोर्ट्स क्लब्स के ज़रिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में कुल मिलाकर 65 करोड़ नौजवान हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए पांच करोड़ युवाओं को जो कुछ मिल रहा है, वह काफी कम नज़र आता है, इसलिए इस विषय पर हम और भी विचार कर रहे हैं।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, काफी हो गया है।

श्री संजय राउत: सर, महाराष्ट्र में 2005-06 में लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से आप दो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ऐसा आपने यहां लिखा है। पहले प्रश्न के माध्यम से मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुम्बई जैसे बड़े महानगर में खेलने के लिए आज मैदान बचे ही नहीं हैं। जब भी कोई जमीन खाली होती है, तो वहां पर या तो कोई मॉल बनता है अथवा बिल्डर्स आकर कोई इमारत खड़ी कर देते हैं। आज मुम्बई में एनटीसी की 18 या 20 मिलें बंद पड़ी हैं। उस जगह पर कोई मॉल या बिल्डिंग बने उससे अच्छा है कि वहां पर कोई मैदान या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने। अगर आप ऐसा कोई कानून बनाएं, जिससे इन जमीनों में से एक-तिहाई हिस्सा स्पोर्ट्स के लिए खेलने के मैदान के लिए दिया जाए जहां बच्चे खेल सकें और खेलों को बढ़ावा मिले।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर तभी दे सकता था यदि स्पोर्ट्स के विषय को कन्करेंट लिस्ट में लाया जाए। जब तक यह विषय राज्य का है तब तक यह बात असंभव है कि यह सदन इस सिलसिले में किसी तरह का भी कोई कानून बनाए ...(**व्यवधान**)।

श्री संजय राउत: नेशनल टैक्सटाइल की जो जमीन हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ...(**व्यवधान**)।

श्री मणि शंकर अय्यर: आपने जो सवाल किया है, उसे इस सदन में नहीं आपको महाराष्ट्र की विधान सभा में उठाना चाहिए और ...(**व्यवधान**)।

श्री संजय राउत: नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन की जो जमीन है ...(**व्यवधान**)।

श्री मणि शंकर अय्यर: अगर आपको यह सुझाव देना हो कि हम स्पोर्ट्स को स्टेट लिस्ट से निकाल कर कन्करेंट लिस्ट में ले आएं तो हमें यह सुझाव दीजिए ताकि हम इस पर विचार कर सकें।

श्री संजय राउत: मंत्री जी नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन की जो जमीन है मैं सिर्फ उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: अब आपका प्रश्न हो गया है।

श्री दत्ता मेघे: महोदय, 2003-04 के बजट में 2,906 करोड़ रुपये का प्रावधान था और आज 480 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पहले केन्द्र इसकी जिम्मेदारी लेता था किन्तु वह जिम्मेदारी अब केंद्र ने टाल दी है, किन्तु महाराष्ट्र के बजट में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। खेल-कूद के लिए आपने जो 480 करोड़ का प्रावधान रखा है, यह नाकाफी है और इसे देखते हुए अभी-अभी आपने जो

भाषण दिया, कम से कम वह भाषण आपको नहीं देना चाहिए था। इस क्षेत्र में आप महाराष्ट्र सरकार को क्या कुछ अतिरिक्त पैसा देने वाले हैं?

कई गांवों में स्कूल एवं कॉलेज तो हैं किन्तु खेलों की कोई सुविधा नहीं है। अभी-अभी आपने खेलों के बारे में जो कुछ कहा है, वही बात हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि यह विषय केन्द्र का क्यों नहीं हो सकता? जब बजट आप देते हैं तो कम से कम उस बजट की निगरानी तो आप करेंगे ही। इस विषय में केवल बोलना ही काफी नहीं है, आप यदि वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो इस पर खर्च होने वाले बजट के हिस्से को बढ़ाइए।

श्री मणि शंकर अय्यर: पहले मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मैं कोई भाषण नहीं दे रहा था, मैं तो सवाल का जवाब तफ़सील में दे रहा था। इतनी तफ़सील में जवाब देने के बावजूद भी माननीय सदस्य को यदि अपने संविधान के बारे में न जानना हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। संविधान में यह लिखा है कि स्पोर्ट्स एक्ट के ...(**व्यवधान**)।

श्री दत्ता मेघे: 1923-24 में संविधान कहां था, तब आपने इतना पैसा खर्च किया और ...(**व्यवधान**)।

श्री मणि शंकर अय्यर: हमारे नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ...(**व्यवधान**)।

श्री दत्ता मेघे: अभी नागालैंड में आपने 900 करोड़ रुपए दिए, वह तो अच्छी बात है ...। किसी स्टेट में दिया नहीं है। देश के अंदर सेंट्रल गवर्मेंट ने नहीं दिया है। ...(**व्यवधान**)।

श्री सभापति: आप जवाब शार्ट में दे दीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: सर, जो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें यह भी बताया गया है कि सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम को कम करके हम जहां तक हो सके उसे ट्रांसफर करें। तो इस दृष्टिकोण में यह निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद ...(**व्यवधान**)

श्री दत्ता मेघे: सर, ...(**व्यवधान**)

श्री मणि शंकर अय्यर: सुन तो लीजिए। ...(**व्यवधान**) यह अजीब चीज है कि हम जवाब दे रहे है ...(**व्यवधान**) आप सुन तो लीजिए, आपने सवाल कर लिया है ...(**व्यवधान**)

श्री दत्ता मेघे: हमको पैसा चाहिए। ...(**व्यवधान**)

श्री मणि शंकर अय्यर: जवाब बस यही है कि इस परिस्थिति को बदलने के लिए हम अपनी तरफ से एक पंचायत युवा खेल अभियान की सोच कर रहे है और यदि आपके नजरिए में स्पोर्ट् जैसे विषय को स्टेट लिस्ट से निकाल कर कांकरेंट लिस्ट में डालना हो तो ऐसा कोई सुझाव हमारे सामने रखिए।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, the hon. Minister has just now mentioned that everything is now left to the States. But, later on, he did mention that there are some other programmes which are coming under the centre. I appreciate it because it is time when the globalisation of everything in the world is taking place, particularly, of the economy, and the whole world is looking at India. They are watching as so what is happening in sports in a country which has more than one billion people. Now, if we leave it to the States only, I don't think we will be able to handle the world situation. I would like to particularly mention that all those who have reached at the world level in the field of sports have come from the villages. But since they have come from the villages,the States are not taking any interest in it. I can vouch for it that not a single district level area today can claim to have any soprts facility. Unless the Central Government has a special provision for this purpose, it will be very difficult to handle this situation. I know he has mentioned about some plans. But I would like to know what is the time-frame of these plans, and what is the estimated budget for this purpose because, if again the budget is reduced from Rs. 2900 crores of Rs. 480 crores...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है , let him speak now. You have made your point.

श्री संतोष बागड़ोदिया: मंत्री जी, बताएं कि बजट कितना है।

श्री सभापति: आपने पूछ लिया, वे बता रहे है।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I am grateful for the support extended by the Hon. Member to the concept that we have in mind of somehow restoring a role for the Central Government in the sports matters. The point that he has made has been taken into consideration by me and will be transmitted to the Ministers concerned and the Planing Commission. Thank you.

**63. [The questioner (Shri Rudra Narayan Pany) was absent. For answer vide page 34.]*

**64. [The questioner (Shri S.S. Ahluwalia) was absent. For answer vide page. 35.]*

Stricter Visa regulations in developed countries

*65. SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: